



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

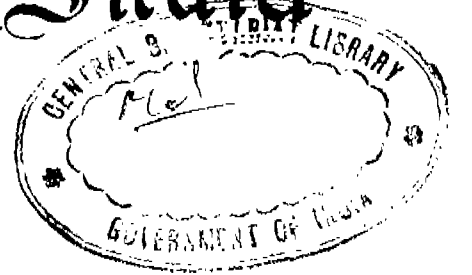
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 6]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2001/पौष 13, 1922

No. 6]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2001/PAUSA 13, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का.आ. 6(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 60 (अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), किसी क्रियाकलाप के विस्तार और आधुनिकीकरण अथवा किसी परियोजना को प्रारम्भ करने पर तब तक कतिपय निर्बंधन और प्रतिबंध अधिरोपित किए थे जब तक कि सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न दे दी गई हो;

और उक्त अधिसूचना तत्पश्चात् का.आ. 356(अ) तारीख 4 मई, 1994, का.आ. 318(अ) तारीख 10 अप्रैल, 1997, का.आ. 73(अ) तारीख 27 जनवरी, 2000 और का.आ. 1119(अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2000 द्वारा संशोधित की गई थी;

और यह पाया गया है कि लघु औद्योगिक इकाइयों, पच्चीस हैक्टर तक पट्टा क्षेत्र वाली खनन परियोजनाएं, राजमार्गों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना और विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण, पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों, दोनों पर नाममात्र का संघात कारित करती है;

और ऐसी परियोजनाओं का पर्यावरण संबंधी संघात का, इस मंत्रालय के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा जन सुनवाई के बिना की गई जानकारी के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है;

अतः अब निम्नलिखित अधिसूचना जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करना चाहती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 60 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उसे लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है।

प्रस्ताव का प्रारूप

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (1) की मद (क) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :—

“तथापि, लघु औद्योगिक इकाइयों (समय-समय पर औद्योगिक नीति में यथा परिभाषित) राजमार्गों को चौड़ा करने और मजबूत बनाने,

पच्चीस हैक्टर तक पट्टा क्षेत्र वाली खनन परियोजनाओं (प्रमुख खनिज) और विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की बाबत लोक सुनवाई अपेक्षित नहीं है।”

[सं. जैड-12013/4/89-आईए, I]

डॉ. पी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल अधिसूचना का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् इसमें का.आ. सं. 356(अ), तारीख 4 मई, 1994, का.आ. 318(अ) तारीख 10 अप्रैल, 1997, का.आ. 73(अ), तारीख 27 जनवरी, 2000 और का.आ. 1119(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2000 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2001

**S.O. 6(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the said notification) issued under sub-section (i) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government imposed certain restrictions and prohibitions on the expansion and modernisation of any activity or the undertaking of any project, unless environment clearance has been granted by the Government;

And whereas the said notification was amended subsequently vide S.O. 356(E) dated the 4th May, 1994, S.O. 318(E) dated the 10th April, 1997, S.O. 73(E) dated the 27th January 2000 and S.O. 1119(E) dated the 13th December, 2000;

And whereas it has been found that Small Scale Industrial Units, Mining Projects with lease area up to twenty five hectares, widening and strengthening of Highways, and modernization of existing Irrigation Projects cause minimal impacts, both on the environment and people living in the vicinity;

And whereas the environment impacts of such projects can be assessed on the basis of the information provided by the project proponents to this Ministry even without a public hearing;

Now, therefore, the following notification which the Central Government proposes to issue in exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003.

### DRAFT PROPOSAL

In the said notification, in paragraph 2, in sub-paragraph I in item (a), the following shall be inserted at the end, namely :—

“However, public hearing is not required in respect of Small Scale Industrial Units (as defined in the Industrial Policy from time to time), widening and strengthening of highways, mining projects (major minerals) with lease area up to twenty-five hectares and modernisation of existing irrigation projects”.

[No. Z-12013/4/89-IA.I]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

**Foot Note.**—The Principal Notification was published vide number S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994 and subsequently amended vide number S.O. 356(E) dated the 4th May, 1994, S.O. 318(E) dated the 10th April, 1997, S.O. 73(E) dated the 27th January, 2000 and S.O. 1119(E) dated the 13th December, 2000.